Title: Need to accord clearance to the proposal of U.P. Government increasing honorarium being paid to Lecturers in vocational colleges.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, देश के सही दिशा में विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था के विस्तार की जितनी आवश्यकता है, उससे भी अधिक जरूरत है कि शिक्षा व्यावसायिक बनाई जाये, वह रोजगारोन्मुखी हो और उसका स्तर उन्नत हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु देश में व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना प्रारम्भ की गई थी। एक दशक पूर्व देश भर में व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया था और दूसरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भ किए गए थे। वर्ा 2000 में इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि इन विद्यालयों में अंशकालिक व पूर्णकालिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाये और इस सलाह के तहत उत्तर प्रदेश में 400-400 उपरोक्त श्रेणी के प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय जो अब 1500 रुपये प्रतिमाह है, उसे बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को जनवरी, 2001 में स्वीकृति हेतु भेजा था, किन्तु अभी तक उपरोक्त मामलों में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त दोनों मामलों में अविलम्ब निर्णय की घोाणा कर व्यावसायिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें।